स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

# परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 352 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 जनवरी 2017 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

## कम वजन के ओएचई स्ट्रक्चर की आपूर्ति

# रेलवे में सेफ्टी का महाघोटाला

सुरेश त्रिपाठी

- कंपनी के साथ मिलीभगत करके मामला रफादफा किए जाने को हो रही है कोशिश
- कोर की कोताही में रेलवे बोर्ड के भी शामिल होने की व्यक्त की जा रही है आशंका

सेंट्रल आर्गेनाईजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन (कोर) तथा कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को मंडी गोविंदगढ़ स्थित जैन स्टील इंडस्ट्री द्वारा आपूर्ति किए गए लाखों टन ओएचई स्टील स्ट्रक्चर निर्धारित और मान्य वजन से कम पाए गए हैं. जबकि कंपनी में राइट्स द्वारा इनका पहला रॉ-मटीरियल के स्तर पर, दूसरा फेब्रिकेशन के स्तर पर और तीसरा गल्वेनाइजिंग के स्तर पर इंस्पेक्शन किया जाता है. इसके बाद भी चौथी बार फाइनल मटीरियल बनने के बाद उनकी किसी एक लॉट से 15-20 स्ट्रक्चर का चयन करके उनका वजन और मोटाई मापी जाती है. इतने इंस्पेक्शन होने के बावजूद यदि कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए यह ओएचई स्टील स्ट्रक्चर कम वजन और कम मोटाई के पाए गए हैं, तो इसमें निश्चित रूप से राइट्स और कोर के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत साबित होती है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए यह कम वजन के ओएचई स्टील स्ट्रक्चर अखिल भारतीय स्तर पर लगभग सभी जोनल रेलों में लगाए गए हैं, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, जबलपुर, कन्नूर, चेन्नई, सिकंदराबाद और जम्मू इत्यादि सेक्शन शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि ऐसी ही सप्लाई के तहत तिरुअनंतपुरम में टीटीसी टाइप का एक शेष पेज 7 पर...

## जीएम पोस्टिंग में रे. बो. की अड़ीबाजी और कैट के आदेश का फंसा पेंच

सुरेश त्रिपाठी

रेलवे की बदहाली का प्रमुख कारण स्टोरकीपर की पुनर्नियुक्ति और रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा जोनल महाप्रबंधकों को कठपुतली बना दिया जाना है

दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधकों की पोस्टिंग में रेलवे बोर्ड की अड़ीबाजी और कैट के आदेश का पेंच फंसा हुआ है. यही कारण है कि पिछले एक महीने से ज्यादा समय से खाली दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की पोस्ट पर किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जबकि इसी महीने 31 जनवरी को उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधकों की दो पोस्टें और खाली होने जा रही हैं. इसके अलावा अगले महीने फरवरी में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की पोस्ट भी खाली होगी, जबकि मेंबर ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड के भी 28 फरवरी को शेष पेज 7 पर...

## दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन के भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य-व्यवहार की जांच

- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रसारित शिकायत पर मजबूर हुआ रेल प्रशासन
- वर्तमान एसडीजीएम के रहते यूनियन के विरुद्ध जांच प्रभावित होने की आशंका

**चेन्नई :** दक्षिण रेलवे प्रशासन ने दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन (एसआरएमयू) के कथित भ्रष्टाचार एवं अनुचित प्रभाव और इसके जोनल महामंत्री एन. कन्हैया को विगत में मिली अनावश्यक सहूलियतों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है. यह जांच दिल्ली के एक पत्रकार गोपी द्वारा 12 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को 9 मुद्दों को लेकर लिखी गई शिकायत को रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण रेलवे को अग्रसारित किए जाने के बाद शुरू हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआरएमयू और उससे संबद्ध फेडरेशन के दबाव में रेलवे बोर्ड इस शिकायत को पिछले पांच महीनों से दबाए बैठा था. पत्रकार गोपी द्वारा फॉलो-अप किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने यह शेष पेज 3 पर...

## उ.प्र. के विकास हेतु 40,453 करोड़ का बजट दिया गया -प्रभु

- रेलमंत्री द्वारा भारतीय रेल की सर्वप्रथम 'हमसफर' एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत
- गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के प्लेटफार्म-9 की दो स्वचालित सीढ़ियों का लोकार्पण

**गोरखपुर ब्यूरो :** रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा रेल भवन, नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग से एवं स्थानीय सांसद महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में भारतीय रेल की सर्वप्रथम 'हमसफर' एक्सप्रेस ट्रेन सं. 2595/12596 एवं 12571/12572 गोरखपुर-आनंदविहार टर्मिनस-गोरखपुर के संचलन का शुभारम्भ हरी झंडी दिखाकर एवं गोरखपुर जं. स्टेशन के प्लेटफार्म-9 की दो स्वचालित सीढ़ियों का लोकार्पण रिमोट से किया गया. इस अवसर पर कांफ्रेंस हॉल, रेल भवन, नई दिल्ली में सांसद पंकज चैधरी एवं सांसद शिवप्रताप शुक्ल भी उपस्थित थे.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करते शेष पेज 7 पर...

# अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी हमेशा खतरनाक होती है

## सतही राजनीतिक शह पर उछलना उससे भी अधिक खतरनाक है !!

सुरेश त्रिपाठी

बहुत पुरानी कहावत है कि 'अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी हमेशा खतरनाक होती है', इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए. इसी तर्ज पर सतही अथवा अस्थाई राजनीतिक शह पर उछलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी कोई स्थाई जमीन नहीं होती है, यह कभी-भी आपके पैरों के नीचे से खिसक सकती है. ऐसे में तब आपको कोई आधार नहीं मिल पाएगा. यह दोनों बातें आरपीएफ के उस सब-इंस्पेक्टर शैलेश तिवारी पर लागू होती हैं, जो कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु की समस्त प्रसिद्धि को सोशल मीडिया पर हैंडल कर रहा था और जिसे उपरोक्त दोनों कारणों की वजह से ही तिनके की तरह रेल भवन से उड़ाकर सुदूर जम्मू-कश्मीर के सोपोर इलाके में फायरिंग रेंज में फेंक दिया गया, जहां अब वह आतंकवादियों के मोर्चे पर है.

शैलेश तिवारी वह व्यक्ति है, जिसकी काबिलियत देखकर रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने न सिर्फ उसे अपना सोशल मीडिया हैंडल सौंपा था, बल्कि अपने पिछले रेल बजट भाषण में भी उसकी तारीफ की थी. इसके बाद देश के तमाम दैनिक अखबारों में उसके फोटो के साथ उसकी बड़ी-बड़ी खबरें भी प्रकाशित हुई थीं. इसके बाद से उसके पांव जमीन पर नहीं थे. बताते हैं कि लोकसभा टीवी से रेलमंत्री के भाषण की उक्त क्लिप निकलवाकर और अपने कुछ नजदीकी लोगों को उसे दिखाकर उसने उनके बीच अपनी अहमियत कायम करने का प्रयास किया था. यह बात रेलमंत्री सेल में बैठी चौकड़ी (कॉकस) को पसंद नहीं आई और वह उसे उसकी हैसियत याद दिलाने का

अवसर तलाश करने लगी थी.

रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि इसी बीच एक दिन रेलमंत्री के ओएसडी ने तिवारी को कोई काम करने के लिए कहा. इस पर बताते हैं कि तिवारी ने ओएसडी से कहा कि वह फिलहाल रेलमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर जरुरी काम में लगा हुआ है, उनका काम कुछ देर बाद किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि बस इसी बात को ओएसडी ने अपना 'प्रेस्टिज इशू' बना लिया और तब रेलमंत्री सेल में बैठी चौकड़ी द्वारा तिवारी को उसकी हैसियत याद दिलाने का निर्णय ले लिया गया. सूत्रों ने बताया कि इस साजिश के तहत सर्वप्रथम ओएसडी एवं ईडीपीजी द्वारा तिवारी के खिलाफ यह कहकर रेलमंत्री के कान भरे गए कि वह उनके नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहा है. संसद में उनके बजट भाषण की क्लिप दिखाकर लोगों को प्रभावित कर रहा है और उनके काम करा देने का उनसे वादा कर रहा है, आदि.. आदि..

सूत्रों का कहना है कि स्वाभाविक रूप से रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने तिवारी को रेलमंत्री सेल से हटाने को कह दिया. रेलमंत्री के कहने भर की देर थी कि तिवारी को फौरन रेल भवन और दिल्ली से भी दूर जम्मू-कश्मीर रेंज में ट्रांसफर कर दिया गया. बताते हैं कि इसके बाद उसने रेलमंत्री से मिलकर अपनी सफाई देने का अत्यंत कठिन प्रयास किया, मगर किसी भी हालत में उक्त चौकड़ी द्वारा उसे रेलमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया गया. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद तिवारी ने कुछ खास लोगों के माध्यम से अपने बेगुनाह होने और रेलमंत्री की सेवा में बने रहने की सिफारिश लगवाई.

इस पर बताते हैं कि रेलमंत्री ने भी कह दिया कि यदि वह वास्तव में सही है, तो उसे उसका ट्रांसफर रद्द करके रेलमंत्री सेल में बने रहने दिया जाए. मगर ओएसडी और ईडीपीजी की चौकड़ी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि तिवारी को किसी भी स्थिति में पुनः रेलमंत्री सेल में एंट्री न मिलने पाए. यही हुआ भी और तिवारी को पुनः रेलमंत्री सेल में नहीं रखा गया. सूत्रों का कहना है कि इसके बाद तिवारी ने रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन के सेल में काम करने की सिफारिश रेल राज्यमंत्री से लगवाई. बताते हैं कि रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने भी उसे अपने सेल में लेने पर अपनी सहमति जता दी थी, मगर वहां भी ओएसडी और ईडीपीजी की चौकड़ी ने उसे एंट्री नहीं करने दी. परिणामस्वरूप उसे जम्मू-कश्मीर जाना पड़ा.

शैलेश तिवारी के रेलमंत्री सेल से चले जाने का परिणाम यह हुआ है कि सोशल मीडिया पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु की प्रसिद्धि घटकर आधी से भी कम हो गई है. अब उनके द्वारा अथवा तिवारी की जगह पर लगाए गए नए व्यक्ति द्वारा जो पॉपुलर ट्वीट्स को रेलमंत्री के नाम पर रिट्विट किया जाता है, ट्वीटर पर उसके जवाब में लोगों द्वारा रेलमंत्री की काफी कड़ी आलोचना की जा रही है. रेलमंत्री के ऐसे ही एक रिट्वीट पर 'रेलसमाचार' ने लिखा कि 'आप रेलवे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आपके सलाहकार मूर्ख हैं, जो कि आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं.' इसके अलावा भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ट्वीटर पर भी रेलमंत्री को कई लोगों ने सलाह दी है कि वे अपने सलाहकारों को बदलें. स्वाभाविक है कि लोगों से ऐसे जवाब की न तो रेलमंत्री को अपेक्षा होती है, और न ही वह इनका जवाब देना या उन पर कोई प्रतिक्रिया जताना जरुरी समझते हैं.

सूत्रों का कहना है कि रेलमंत्री सेल में सक्रिय इस चौकड़ी के सदस्य ओएसडी द्वारा जहां अपनी पैरेंट कंपनी, जहां से वह आए हैं, को लाभ दिलाने के लिए रेलमंत्री से 'रेल विकास शिविर' जैसे अनुत्पादक एवं फालतू आयोजन करवाए जा रहे हैं. वहीं ईडीपीजी, जिसका उल्लेख रेल भवन के लोग शार्ट में 'पाजी' कहकर करते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रेलमंत्री तक नहीं पहुंचना चाहिए, जो कि रेलवे की तमाम जमीनी हकीकतों और यात्रियों की मूलभूत ओपिनियन से उन्हें अवगत करा सके.

सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि इस चौकड़ी द्वारा रेलमंत्री को लगभग हर दिन फालतू उदघाटनों और अनावश्यक दौरों में व्यस्त रखा जाता है. उल्लेखनीय है कि रेलवे के लाखों-करोड़ों रुपए ऐसे एक-एक उदघाटन में खर्च हो रहे हैं, जिनका कोई रिटर्न रेलवे को नहीं मिल रहा है. इसके अलावा इनके चलते अब सुरेश प्रभु की तुलना ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव से की जाने लगी है, जो पार्टी हितों के लिए रेलवे के खर्च पर लोक-लुभावन काम किया करते थे.

सूत्रों का कहना है कि ईडीपीजी को पार्टी द्वारा रेलमंत्री सुरेश प्रभु पर यह कहकर थोपा गया है कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेता का दामाद है, जो कि पार्टी हितों के लिए उन्हें बेहतर सलाह देगा, मगर अब यही दामाद भीतर-भीतर सुरेश प्रभु के खिलाफ माहौल बनाने और उनकी जड़ें कुतरने के लिए काम कर रहा है. सूत्रों ने बताया कि विगत में एक टीवी चैनल को रेलमंत्री कक्ष में ही इंटरव्यू देने के लिए श्री प्रभु को इसी दामाद ने तैयार किया था, मगर जब उसी चैनल ने श्री प्रभु से कुछ ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए, जिनका जवाब देते नहीं बना, तब श्री प्रभु की स्थिति काफी असमंजस भरी हो गई थी. बताते हैं कि सुरेश प्रभु से पूछने के लिए उक्त चैनल को संबंधित सवाल इसी दामाद और ओएसडी ने बताए थे. उसके बाद से सुरेश प्रभु ने अब तक किसी टीवी चैनल को व्यक्तिगत इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं जुटी पाई है.

उपरोक्त तमाम तथ्यों के आधार पर सूत्रों ने अंत में तमाम रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह देते हुए यही कहा कि उपरोक्त पुरानी कहावत पर अमल करते हुए अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से हमेशा बचकर रहें तथा किसी को भी सतही राजनीतिक शह पर उछलना नहीं

# सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट, सांताक्रुज पूर्व के अंदर अनधिकृत निर्माण

### ■ विजिलेंस जांच में इंस्टिट्यूट के कैशियर के पास मिली दो लाख की पुरानी करेंसी

**मुंबई :** पश्चिम रेलवे के सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट, सांताक्रुज पूर्व में जब से एक वर्ग विशेष के कर्मचारियों का कब्जा हुआ है, तब से यह इंस्टिट्यूट विवादों में घिरा हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल इंस्टिट्यूट के अंदर इसके पदाधिकारियों द्वारा अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है. बताते हैं कि उक्त अनधिकृत निर्माण की प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई है. जबकि इंस्टिट्यूट में पहले से ही तल एवं पहली मंजिल की इमारत सहित एक बड़ा हॉल, दो एसी कमरे और एक कार्यालय उपलब्ध है.

पता चला है कि 15 दिसंबर 2016 को इंस्टिट्यूट की तमाम अनियमितताओं के बारे में हुई कई शिकायतों पर पश्चिम रेलवे विजिलेंस की एक टीम ने इंस्टिट्यूट के कामकाज संबंधी गतिविधियों की जांच की. इस विजिलेंस जांच के समय इंस्टिट्यूट के तीन पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने बतौर गवाह जॉइंट रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विजिलेंस जांच में इंस्टिट्यूट के कोषाध्यक्ष के पास लगभग दो लाख से ज्यादा की पुरानी नकद करेंसी बरामद हुई. जिसे विजिलेंस ने इंस्टिट्यूट के बैंक

**सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट, सांताक्रुज पूर्व के अंदर किया जा रहा अनधिकृत निर्माण.**

एकाउंट में डिपाजिट कराने के बाद उसकी रसीद विजिलेंस के पास जमा करने को कहा था.

बताते हैं कि इंस्टिट्यूट के कोषाध्यक्ष ने इंस्टिट्यूट की यह नकद राशि अपने घर पर रखी हुई थी, जहां खुद विजिलेंस को जाकर उक्त राशि बरामद करनी पड़ी. पता चला है कि इस राशि को इंस्टिट्यूट के बैंक खाते में जमा कराने के बजाय उसे अनधिकृत रूप से घर पर रखा गया था. इस राशि की कोई रसीदें भी बरामद नहीं हुई हैं. इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि इंस्टिट्यूट के हॉल आदि की बुकिंग की राशि नकद में ली जाती है, जिसकी कोई रसीद जारी नहीं की जाती है. इस सबके पीछे इंस्टिट्यूट के पदाधिकारियों का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है.

**सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूट, कल्याण पूर्व के अंदर अनधिकृत रूप से ठेकेदार का स्थाई कब्जा और उसके द्वारा स्थाई रूप से लगाए गए तम्बू-कनात.**

तथापि, यह आश्चर्य अवश्य व्यक्त किया जा रहा है कि जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी थी, तब 15 दिसंबर 2016 तक इंस्टिट्यूट के कोषाध्यक्ष द्वारा उक्त राशि इंस्टिट्यूट के बैंक एकाउंट में क्यों नहीं जमा कराई गई? यह नकद पुरानी करेंसी लगभग डेढ़ महीने तक कोषाध्यक्ष द्वारा अपने घर पर क्यों रखी गई? बताते हैं कि शादी-ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों की बुकिंग के लिए इंस्टिट्यूट के कोषाध्यक्ष द्वारा बुकिंग कर्ताओं से 10

### ■ कल्याण रेलवे इंस्टिट्यूट में स्थाई रूप से कैटरिंग एवं कनात ठेकेदार का अवैध कब्जा

हजार रुपए की नकद राशि ली जाती है, मगर इस नकद राशि के लेनदेन की कोई रसीद उन्हें जारी नहीं की जाती है. यह तरीका पिछले करीब एक साल से चल रहा है. इसके अलावा इंस्टिट्यूट में फंड की बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी किए जाने की चर्चा है.

इस संबंध में मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे के सीनियर डीपीओ, जो कि इंस्टिट्यूट के संरक्षक हैं, तथा मंडल रेल प्रबंधक दोनों से 'रेलवे समाचार' ने उनके मोबाइल पर संपर्क किया, मगर दोनों अधिकारियों में से किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई. कर्मचारियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की इसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनदेखी के कारण लगभग सभी रेलवे इंस्टिट्यूट्स में भारी वित्तीय धांधली चल रही है और संबंधित लोगों ने इंस्टिट्यूट को अवैध रूप से अपनी कमाई का जरिया बना लिया है. इसी प्रकार मध्य रेलवे के कल्याण स्थित रेलवे इंस्टिट्यूट (रेलवे हॉस्पिटल के सामने) को स्थाई रूप से कैटरिंग एवं कनात ठेकेदार को सौंप दिया गया है, जहां उसने स्थाई रूप से तम्बू-कनात लगाकर अपनी ठेकेदारी चला रखी है.

## सीनि.डीसीएम/त्रिची के साथ मारपीट करने वाले

# यूनियन पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर

**तिरुचिरापल्ली :** मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पिछले हफ्ते तिरुचिरापल्ली की कैंटोनमेंट पुलिस को दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन (एसआरएमयू) के उन 10 पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद और 30 अन्य अनजान कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर गहराई से जांच किए जाने का आदेश दिया है, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2016 को तिरुचिरापल्ली (त्रिची) मंडल, दक्षिण रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अरुण थॉमस के चैम्बर में अनधिकार घुसकर उनके साथ मारपीट, धक्कामुक्की और गाली-गलौज करने सहित उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी.

श्री थॉमस ने हाई कोर्ट का रुख तब किया था, जब यूनियन एवं उसके परिचित प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के दबाव में पुलिस उक्त यूनियन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी, बल्कि उनके खिलाफ ही कर्मचारियों/यूनियन की शिकायत भी दर्ज कर ली थी. हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट पुलिस, त्रिची को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (हंगामा करना), 447 (अपराधिक घुसपैठ), 294-बी (सार्वजनिक स्थान पर अभद्र एवं असंवैधानिक भाषा का प्रयोग) और 506/आई (जान से मारने की अपराधिक धमकी) के तहत अपराधिक मामला दर्ज कर गंभीरतापूर्वक जांच करने का आदेश दिया है. श्री थॉमस ने अपनी लिखित शिकायत में यूनियन के 10 मंडल पदाधिकारियों को नामजद किया है. इसके अलावा 30 अन्य अनजान कार्यकर्ताओं के

**मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने दिया है पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश**

विरुद्ध भी उन्होंने शिकायत की है, जो कि हंगामा करने और धमकी देने में शामिल थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री थॉमस की इस एफआईआर में पार्सल क्लर्क एवं सहायक मंडल सचिव, एसआरएमयू/त्रिची इसाक जॉनसन, चीफ टिकट इंस्पेक्टर/त्रिची वी. थमाराई सेल्वन, चीफ टिकट इंस्पेक्टर/मयिलाडूथूराई बी. जयचंद्रन, इन्क्वारी-कम-रिजर्वेशन क्लर्क/त्रिची सैय्यद ताजुद्दीन असलम, डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल/त्रिची की मैट्रन शांति थंगम, फिटर/त्रिची एम. ए. मार्टिन को नामजद किया गया है. जबकि 30 अन्य के नाम अनजान बताए गए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की तरफ से भी श्री थॉमस के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने दोनों पार्टियों को सीएसआर रिसिप्ट जारी की है. बताते हैं की पुलिस ने अब तक उक्त कर्मचारियों में से किसी की भी गिरफ़्तारी नहीं की है.

उल्लेखनीय है कि सीनियर डीसीएम/त्रिची अरुण थॉमस के साथ उनके चैम्बर में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाली इस घटना के बाद 11 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था और इनमें से चार कर्मचारियों का इंटर डिवीजन ट्रांसफर किया गया था, जिसे सीआरबी ने रुकवा दिया था. बताते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त कई टिकट चेकिंग स्टाफ के लिंक ड्यूटी रोस्टर का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी. प्रशासन द्वारा त्रिची मंडल में सालों बाद टिकट चेकिंग स्टाफ सहित बुकिंग स्टाफ, आरक्षण एवं पार्सल स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर बनाए जाने से नाराज कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों का कहना था कि उनसे पूछे बिना ही नया लिंक ड्यूटी रोस्टर बनाया गया? जबकि यह लिंक ड्यूटी रोस्टर दक्षिण रेलवे मुख्यालय द्वारा बनाया गया था.

# पूर्वोत्तर रेलवे शीघ्र ही पूर्णतः बड़ी लाइन की रेलवे हो जाएगी –महाप्रबंधक

■ नववर्ष के अवसर पर एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन का मिलन समारोह संपन्न

**गोरखपुर ब्यूरो :** पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में 2 जनवरी को के. आर. चटर्जी मेमोरियल हॉल, गोरखपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) भारतीय रेल की एक पुरानी यूनियन है. रेल के विकास में इसका पर्याप्त योगदान रहा है. श्री मिश्र ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारी संगठन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनका आपसी सहयोग किसी भी संस्थान के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने नरमू द्वारा पिछले दो वर्षों में मिले सहयोग की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में इसका सहयोग रेल प्रशासन को मिलता रहेगा.

इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने कहा कि विगत दो वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे में आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा नई लाइन निर्माण के क्षेत्र में अनेक स्मरणीय कार्य किए गए हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग सभी रेल खंडों का आमान परिवर्तन हो चुका है या उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है. वह दिन दूर नहीं जब पूर्वोत्तर रेलवे पूर्णतः बड़ी लाइन की रेलवे हो जाएगी. इसका प्रत्यक्ष लाभ रेल परिवहन में सुधार तथा मालगाड़ियों के तीव्र संचालन में परिलक्षित होगा. विद्युतीकरण के क्षेत्र में विगत वर्षों की उपलब्धियों को दूरगामी परिणाम देने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही अनेक स्टेशनों को टर्मिनल तथा सेटेलाइट स्टेशन में विकसित किया जा रहा है.

महाप्रबंधक श्री मिश्र ने यात्री सुविधा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर एस्कैलेटर, लिफ्ट, वाई-फाई, ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड तथा आवश्यकतानुसार आईएसएस का प्रावधान किया जा रहा है. रेल कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखे जाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति, स्टाफ क्वार्टरों में सुधार सहित अनेक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की किसी भी समस्या का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने इस अवसर पर सभी को नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं भी दीं.

नरमू के महामंत्री के. एल. गुप्ता ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर मिलन समारोह का आयोजन उनकी यूनियन की परम्परा रही है, जो अवध तिरहुत (ओटी) रेलवे के समय से चली आ रही है. पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की कार्यदक्षता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा से भरे श्री मिश्र की सोच आधुनिक है, जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे पर अनेक योजनाओं को मूर्त रूप मिल सका. उन्होंने आशा व्यक्त की कि महाप्रबंधक श्री मिश्र द्वारा लिए गए निर्णयों का जमीनी स्तर पर अक्षरशः पालन होता रहेगा. उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. समारोह में वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं नरमू के पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे.

# दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन के भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य-व्यवहार की जांच...

**पेज 1 का शेष...** शिकायत हाल ही में दक्षिण रेलवे को जांच करके रिपोर्ट देने हेतु भेजी है.

पता चला है कि विजिलेंस विभाग ने सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त शिकायत संबंधित विभागों को भेजकर उनसे रिपोर्ट मांगी है. परंतु सूत्रों का कहना है कि वर्तमान एसडीजीएम/द.रे. द्वारा शिकायत की जांच में देरी किए जाने की यह उनकी एक युक्ति है, क्योंकि ऐसी शिकायतों पर विभागों से रिपोर्ट मांगे जाने का सीवीसी के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई कड़ा निर्देश नहीं है. यह जांच खुद विजिलेंस को करके उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड विजिलेंस को भेजनी है. बताते हैं कि वर्तमान एसडीजीएम का रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2017 को है, इसीलिए वह अपनी सेवानिवृत्ति तक यूनियन की गुडबुक में बने रहने के लिए जांच को तब तक लटकाए रखना चाहते हैं.

बताते हैं कि इसके लिए एसडीजीएम ने पहले अपने मातहतों को पत्रकार गोपी से उक्त शिकायत उनके द्वारा ही किए जाने की पुष्टि किए जाने को कहा. इस पर जब कई बार गोपी को फोन करके और पत्र लिखकर शिकायत की पुष्टि करने को कहा गया, तो वह संबंधित विजिलेंस वालों पर भड़क गए और कहा कि जब उन्होंने कई बार अपनी शिकायत की पुष्टि कर दी है, तो बार-बार उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से अग्रसारित शिकायत के गलत होने की कोई आशंका विजिलेंस को हो सकती है? इस तरह एसडीजीएम द्वारा करीब एक महीने तक उक्त शिकायत को यूं ही भटकाया जा रहा था. अंततः उन्होंने सभी संबंधित विभागों को उक्त शिकायत से संबंधित रिपोर्ट दिए जाने का हथकंडा अपनाया.

स्थानीय अखबारों में छपी खबर के अनुसार एसआरएमयू के महामंत्री एन. कन्हैया उर्फ 'पार्सल पोटर' के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूनियन अथवा इसके किसी पदाधिकारी विशेष के विरुद्ध ऐसी कोई विजिलेंस जांच की जा रही है, इस बारे में यूनियन को कोई जानकारी नहीं है. इस पर कई कर्मचारियों को कहना है कि एक यूनियन का मामूली महामंत्री भी अब राजनीतिक पार्टियों की तरह अपना प्रवक्ता और किसी सेलेब्रिटी की तरह अपने आगे-पीछे कई-कई बाउंसर रखने लगा है. ऐसे में मीडिया को अपना बयान खुद देने में उसको शर्म महसूस होती है?

गोपी की शिकायत में यूनियन के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा उनका निर्धारित कोई काम नहीं किया जाना, कार्यालय नहीं आना, गैर-कानूनी रूप से रेलवे संपत्ति पर कब्जा करना, यूनियन की गैर-जरुरी मांगों को न मानने वाले अधिकारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और उन्हें परेशान किया जाना इत्यादि हैं. इसके अलावा शिकायत में एसआरएमयू के खुले भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है. उल्लेखनीय है कि यूनियन के नाम पर कथित असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और दक्षिण रेलवे के ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए दहशत का पर्याय बन गया एन. कन्हैया ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) का कार्याध्यक्ष भी है, जो कि एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि यूनियन के अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करके लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारी न तो

रेलवे का अपना निर्धारित काम करते हैं, और न ही कार्यालय आते हैं. शिकायत में यूनियन पर रेलवे संपत्ति पर गैर-कानूनी कब्जा करने सहित उसको भाड़े पर दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है. इसके अलावा एसआरएमयू द्वारा अधिकांश इमरजेंसी कोटा (ईक्यू) वितरित किए जाने का भी आरोप है, जिसके बारे में एक चीफ रिजर्वेशन इंस्पेक्टर (सीआरआई) ने लिखित मामला दर्ज कराया था.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एसआरएमयू का महामंत्री एन. कन्हैया अक्सर दिल्ली और हरियाणा जैसे अन्य कई राज्यों के सांसदों से उसके अनावश्यक दबाव को न मानने वाले दक्षिण रेलवे के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे बोर्ड को फर्जी शिकायतें करवाता है और इस तरह से वह ऐसे अधिकारियों का कैरियर ख़राब करता रहा है. शिकायत में कहा गया है कि ऐसे ही एक अधिकारी एवं उसके परिवार को यूनियन पदाधिकारियों द्वारा जान से मार देने और बरबाद कर दिए जाने संबंधी दी गई धमकी से लगभग सभी सतर्कता एजेंसियां अवगत हैं.

शिकायत में यूनियन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि यदि किसी अधिकारी ने गलत चीजों को ठीक करने की कोशिश की, या यूनियन की अनुचित मांगों को मानने से इंकार किया, तो यूनियन द्वारा या तो उसकी पिटाई की गई अथवा उसके खिलाफ एट्रोसिटी या छेड़छाड़ के फर्जी आरोप लगाकर उसे फंसाया गया, या फिर दक्षिण रेलवे से बाहर उसका ट्रांसफर करा दिया गया. शिकायत में स्थानीय अधिकारियों द्वारा कन्हैया का फेवर किए जाने का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ऐसे सभी अधिकारियों की पहचान करके उन्हें अविलंब दक्षिण रेलवे से बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी पहचान न उजागर किए जाने की शर्त पर कहा कि यदि यूनियन के विरुद्ध ईमानदारी से यह विजिलेंस जांच संपन्न हुई, तो यूनियन की मान्यता छिन जाना निश्चित है. इसके अलावा उसका भ्रष्टाचार भी उजागर होगा और इसके साथ ही उसके पदाधिकारियों तथा यूनियन की शह पर रेलवे का निर्धारित काम न करके मुफ्त का वेतन हड़पने वाले तथाकथित यूनियन कार्यकर्ताओं की पोल भी खुलेगी. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि यूनियन के घोर समर्थक वर्तमान एसडीजीएम, सीपीओ और सीओएम को तुरंत उनके पदों से अन्यत्र ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

# सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी तीनों न सिर्फ अपने आपमें संपूर्ण बोध वाक्य हैं, बल्कि भारतीय रेल की सबसे पहली प्राथमिकता भी यही है. जबकि वर्तमान में भारतीय रेल से यही तीनों चीजें सिरे से गायब हो गई हैं. सेफ्टी की हालत यह है कि उत्तर मध्य रेलवे के एक ही सेक्शन में लगभग दो महीनों के अंतराल में दो बड़ी और भीषण रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. उधर पूर्व मध्य रेलवे के लगभग सभी मंडलों में पिछले दिनों डिरेलमेंट हुए हैं. मध्य रेलवे में तो यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा है, जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी मालगाड़ियों के कई डिरेलमेंट और यात्री ट्रेनों की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इसी प्रकार अन्य जोनल रेलों में भी लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं. रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल का सेफ्टी ऑडिट करने के लिए राइट्स की नियुक्ति की है. जबकि जिंदगी भर एक अंकगड़क या अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड द्वारा एक और सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया है. आखिर इतनी सारी सेफ्टी कमेटियों के गठन से ही क्या रेलवे की सेफ्टी सुधर जाएगी? जबकि शुंगलु, वांचू, खन्ना और काकोड़कर जैसे विषय-विशेषज्ञों की विशेष सेफ्टी रिपोर्ट्स रेलवे बोर्ड की अलमारियों में वर्षों से पड़ी धूल फांक रही हैं. इसके अलावा हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में सेफ्टी विशेषज्ञ रेल अधिकारियों की एक तीन सदस्यीय सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही रेलवे बोर्ड को सौंपी जाने वाली है. ऐसे में एक विनोद राय की अध्यक्षता में एक और सेफ्टी कमेटी के गठन का औचित्य क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त विनोद राय की सेफ्टी के मामले में विशेषज्ञता क्या है? क्या इसका मतलब यह लगाया जाना चाहिए कि एक अकाउंटेंट अपने जैसे ही दूसरे अकाउंटेंट के अलावा किसी अन्य को रेलवे का विशेषज्ञ मानता ही नहीं है? अथवा यह सारी कवायद पूरी दुनिया सहित पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही है? पूरी भारतीय रेल पिछले ढ़ाई सालों से प्रचार तंत्र पर चल रही है. जबकि इस दरम्यान जमीनी स्तर पर भारतीय रेल में कोई भी सुदृढ़ कार्य नहीं किया गया है. रेलमंत्री की यह सारी मूर्खतापूर्ण कवायदें देखकर रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी न सिर्फ खीझ रहे हैं, बल्कि वह अपने बाल नोचने तक की स्थिति में पहुंच गए हैं. जिस तरह रेलवे के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी रेलमंत्री स्वयं को रेलवे का विशेषज्ञ समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह पुनर्नियुक्त सीआरबी उर्फ स्टोरकीपर द्वारा अपने और अपने कैडर के अलावा बाकी सभी कैडर के रेल अधिकारियों को मूर्ख समझकर कार्य-व्यवहार किया जा रहा है. इसके चलते चालू वित्तवर्ष 2016-17 के पिछले 9 महीनों के दौरान माल लदान में लगभग 92 हजार मीट्रिक टन की कमी आई है और भारतीय रेल लोडिंग के मामले में अपने घोषित लक्ष्य से बहुत पीछे है. जहां गुड्स यार्डों की हालत खस्ता है, वहां न लाइट है, न पानी है, और न ही कोई सही-सलामत अप्रोच रोड ही है, जबकि यहां से भारतीय रेल प्रतिमाह-प्रतिवर्ष करोड़ों-अरबों रुपए की कमाई करती है, वहीं यात्री सुविधा (पैसेंजर एमिनिटी) में लाखों करोड़ रुपए झोंके जा रहे हैं और इस तरह एलआईसी से मिले डेढ़ लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है. क्या इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि बुनियादी विकास योजनाओं के बजाय यात्री सुविधा के कार्यों में 'कमीशन' ज्यादा मिलता है? जबकि वास्तव में इस कर्ज का उपयोग खस्ताहाल रेल लाइनों और माल गोदामों तथा गुड्स यार्डों की हालत सुधारने के लिए किया जाना चाहिए था. यदि रेलमंत्री की नजर में पैसा कमाना ही सर्वश्रेष्ठ टारगेट है, तो सर्वप्रथम भारतीय रेल को एक कमर्शियल आर्गेनाईजेशन घोषित किया जाना चाहिए. और यदि रेलमंत्री एवं सीआरबी की नीतियां सही हैं, तो भारतीय रेल घाटे में क्यों जा रही है. विज्ञापनों से कमाई का लक्ष्य चालू वर्ष में करीब 1700 करोड़ रुपए का रखा गया है, मगर यह लक्ष्य न कभी प्राप्त किया जा सकता और न ही आगे कभी प्राप्त किया जा सकेगा. इसका कारण यह है कि रेल अधिकारी रेल चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, न कि परचून की दूकान चलाने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है. यदि रेलवे को विज्ञापनों से कमाई करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए और उसके बाद उक्त क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए. वर्तमान रेल अधिकारियों को विज्ञापन से कमाई करने का न तो कोई अनुभव है और न ही उन्हें इसका कोई प्रशिक्षण दिया गया है. ऐसे में वह विज्ञापन से कमाई कैसे ला सकते हैं?

भारतीय रेल की प्रमुख गतिविधि (कोर एक्टिविटी) ट्रांसपोर्टेशन है. मगर इस मुख्य गतिविधि को पिछले ढ़ाई सालों से साइड लाइन में डाल दिया गया है. इसकी जगह भारतीय रेल में वह सारी फालतू गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनका इसकी मुख्य गतिविधि (ट्रांसपोर्टेशन) से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है. आदर्श और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, स्टेशनों पर मॉल और फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स स्थापित किए जा रहे हैं. मेडिकल स्टोर्स और पालनाघर बनाए जा रहे हैं. स्टेशनों को वाई-फाई किया जा रहा है. एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं. टिकट चेकिंग कर्मचारियों और स्टेशन मास्टरों की वर्दी चमकाई जा रही है. सोशल मीडिया पर शिकायतों का पिटारा खोल दिए जाने को एकाउंटेंट्स की अपनी प्रचार नीति का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसके लिए काबिल से काबिल रेल अधिकारियों का इस्तेमाल यात्रियों को दूध की बोतल, जुकाम की सुंघनी और सिरदर्द की गोली पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. उन्हें साफ-सफाई में झोंक दिया गया है. मीटिंग्स और फालतू चर्चाओं में कीमती समय जाया किया जा रहा है. मगर गाड़ियां समय पर चलें और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचें, इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है. गाड़ियों की लेट-लतीफी की स्थिति शेष पेज 6 पर...

# प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक खुला पत्र

## 'यदि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए'

**माननीय श्री मोदी जी,**

मैं भारत के उन 125 करोड़ लोगों में से एक हूं, जिनकी आप भारत में और विदेशों में अपने सार्वजनिक भाषणों में सराहना करते रहते हैं. मैं इस पत्र की शुरूआत में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है.

सर्वप्रथम मैं अभी हाल ही में आपके द्वारा लिए गए नोटबंदी के साहसिक और ऐतिहासिक विराट फैसले के लिए आपको साधुवाद देता हूं. आपके इस एक फैसले से सर्वथा निराश हो चले विशाल भारत देश में अचानक एक नई आशा का संचार हुआ है. मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार का फैसला लेना एक प्रधानमंत्री होते हुए भी आपके लिए कितना कठिन रहा होगा. 70 साल से इक्कट्ठी हुई भ्रष्टाचार की गंदगी की सफाई की तरफ शायद ही कोई और एक कार्यवाही इतना कारगर हो सकती थी. यद्यपि अनेकों अर्थशास्त्री इस कदम की आलोचना कर रहे हैं.

मोदी जी, अपको और हम सब को यह समझना होगा कि आपका यह बहुत भारी फैसला भी गहरी जड़ें जमाए हुए भ्रष्टाचार रूपी पेड़ के फलों पर ही प्रहार करता है, जिसकी जड़ें नोटबंदी के इस विराट फैसले के बावजूद जस की तस मजबूत हैं. ये जड़ें आपके ढ़ाई साल के कार्यकाल में और अधिक मजबूत हुई हैं, जिसमें आपका भी यत्किंचित योगदान रहा है. हम सब को समझना होगा कि इन जड़ों को सबसे ज्यादा गहराई और ताकत हमारी बिल्कुल लचर न्याय प्रणाली और व्यवस्था से मिलती है. एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आपने और आपकी पार्टी ने तो स्वयं अन्याय की एक बेजोड़ मिसाल तब पेश की जब भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अपने ही सांसद कीर्ति आजाद को आप लोगों ने पार्टी से निलंबित कर दिया. जिस संस्था और जिस बड़े नेता का भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया था, उनके विरूद्ध या आपके कार्यकाल में अपने भ्रष्टाचार के लिए चर्चा में आए किसी भी बड़े नेता या उद्योगपति, आपकी पार्टी से जुड़े हों या विपक्ष से जुड़े हों, के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है.

**रेलवे में सुधार के लिए कई समितियां बनी, परंतु जमीनी कार्य कुछ नहीं हुआ**

मोदी जी, यह सही है कि नोटबंदी के आपके फैसले से एक बड़ी मात्रा में कालाधन नष्ट होगा, परंतु हमको यह भी समझना होगा कि नोटबंदी के कारण बैंकों में जमा होने वाला पैसा कालाधन ही नहीं, अपितु लोगों के पास घरों में रखा हुआ निष्क्रिय धन भी है.

कालेधन पर बनी एसआईटी ने एक वर्ष से अधिक पहले बताया था कि हर वर्ष तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक कालेधन का लेन-देन क्रिकेट में सट्टे के परिणाम स्वरूप होता है. मैं सीधे पत्रों द्वारा पिछले दो वर्षों में बार-बार आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार यह बहुत भारी व्यभिचार, भ्रष्टाचार और घोटाला फिक्स की हुई क्रिकेट के माध्यम से चल रहा है, जिसमें सभी खिलाड़ी, क्रिकेट प्रबंधक, क्रिकेट कोच, और अनेकों प्रख्यात लोग, उद्योगपति, मंत्री और राजनीतिज्ञ लिप्त हैं. सब पर उंगली उठाने वाला मीडिया इस महाघोटाले की रीढ़ की हड्डी है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका संगरक्षक. यह लिंक आपकी याददाश्त ताजा कर देगा- http:// www. diamondbook.in/underworld-cup.html I

इस संस्थागत व्यापक महाघोटाले के प्रति आप नितांत उदासीन रहे हैं, जिसकी जवाबदेही आप पर हमेशा बनी रहेगी. यदि आपने इस विषय में कुछ कार्यवाही की होती, तो भ्रष्टाचार के विशाल पेड़ की जड़ों पर भी एक गहरा प्रहार होता.

भारतीय पुलिस और मीडिया के अनुसार क्रिकेट के इस महाघोटाले का सीधा लाभ दाऊद इब्राहीम को पहुंचता है. फिर भी आप न केवल इसके प्रति उदासीन रहे हैं, वरन् इसको आपका वरदहस्त भी प्राप्त रहा है. केपीएस और टीएनपीएल जैसी नई--नई टी-20 लीगों के माध्यम से यह महाघोटाला और बढ़ता ही जा रहा है. यदि अब भी आप और आपकी सरकार करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए इस महाघोटाले के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार के मजबूत पेड़ में नए और अधिक रसीले फल लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. एक व्यापक स्तर पर भ्रष्ट आचरण बरकरार रहेगा.

मुझे समझ नहीं आता कि एक महाघोटाले पर तालियां बजाता देश कभी भी महान कैसे हो सकता है? मोदी जी, जहां आप एक ओर दम भरते हैं कि बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर नामी-गिरामी भ्रष्टों को आपका और आपकी सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा है, जिनमें कुछ नाम अरुण जेटली, बंसुधरा राजे सिंधिया, विजय माल्या आदि हैं. अभी हाल ही में आपकी कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बदलाव से नौकरशाही में भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा.

मोदी जी, अभी हाल ही में आपने रेलवे व्यवस्था में सुधार के लिए सूरजकुंड में एक विशाल रेल विकास शिविर का आयोजन करवाया. दुर्भाग्यवश उसी दिन एक बहुत बड़ी रेलवे दुर्घटना हुई, जिसमें करीब डेढ़ सौ भारतवासियों ने दर्दनाक तरीके से प्राण गंवाए और सैंकड़ों घायल हुए. (इसके साथ ही मात्र एक महीने के अंदर उसी रेल खंड में दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना फिर हो गई.) इससे आपको समझ जाना चाहिए कि सुधार बड़ी-बड़ी बातों से नहीं, वरन् जमींनी काम से होते हैं. रेलवे में सुधार के लिए बहुत समितियां बनी हैं और उनकी रिपोर्टों पर चर्चाएं भी हुई हैं, परंतु जमीनी कार्य कुछ नहीं हुआ. रेलवे नौकरी में रहते हुए स्वयं मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें संस्थागत भ्रष्टाचार द्वारा रेलवे की खरीदारी में हो रहे सालाना पांच हजार करोड़ रुपए के रिसाव को रोकने के लिए क्रियात्मक उपयोगी सुझाव दिए गए थे.

वर्तमान पुनर्नियुक्त रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ए. के. मितल स्वयं इस समिति के सदस्य थे, पर इस समिति की रिपोर्ट में संस्थागत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दिए गए संस्थागत सुधारों के सुझावों के प्रति भी आपकी सरकार उदासीन रही है, जबकि आप और आपके मंत्री आपकी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी होने का ढ़ोल पीटते रहे हैं. बताए गए भारी रिसाव की पुष्टि मेट्रो मैन ई. श्रीधरन ने भी तदोपरांत अपनी एक रिपोर्ट में की है. तथापि, रेलवे में यह सुझाव और सुधार आज तक लागू नहीं किए गए हैं.

ऐसे अनेकों संस्थागत भ्रष्टाचार भारत में फल-फूल रहे हैं. इनको नजरअंदाज कर बड़ी-बड़ी बातें करते हुए आप जनता को मूर्ख बनाते ही प्रतीत होते हैं. केवल वाकपटुता और ड्रामे से कोई बात नहीं बनती. विश्वास कीजिए कोई भी जनता को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकता. आपको मालूम ही होगा कि नोटबंदी के बाद, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से, या उसके बिना, बड़ी संख्या में कालेधन को सफ़ेद करने में लोगों ने कालाधन कमाना शुरू भी कर दिया है.

मोदी जी, आप यह जरूर मानेंगे कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आपकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगता है और बहुत से लोगों को आपकी नीयत पर शक हो रहा है. इसकी झलक साफतौर पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. साथ ही आपके विरोधी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नोटबंदी से पूर्व आपने इस बात की जानकारी कुछ उद्योगपतियों और दोस्तों को दे दी थी. यही कारण है कि आपके इरादे के खिलाफ अफवाहों का बाजार गर्म है. यह कहा जा रहा है कि आपका असली उद्देश्य बैंकों में पैसा लाना था, जिसका लाभ आगे आपके उद्योगपति मित्रों को मिल सके. हम यह आशा करते हैं कि इस तरह की बातें गलत साबित हों और आप गोवा में दिया अपना वचन निभाएंगे.

बड़ी संख्या में यह कहने वाले लोग हैं कि सबसे पहले स्विस बैंकों में जमा धन वापस लाया जाना चाहिए. मैं ऐसे लोगों की इस सोच से सहमत नहीं हूं कि यदि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए.

गोवा में आपकी आंखों में यह कहते समय आंसू आ गए थे कि आपने देश की खातिर अपने घर और परिवार का त्याग कर दिया. हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप इस बात को मानेंगे कि इस त्याग के कारण ही आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च नेता चुना गया है. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों तक का बलिदान किया, पर वे आप जैसे भाग्यशाली नहीं थे कि उन्हें उचित सम्मान मिलता.

यह पत्र लिखने का उद्देश्य आपकी छवि को मलिन करना नहीं है, बल्कि आपको और देश को वास्तविकता से अवगत कराना है. आप पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ें और भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े लोगों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें. विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा यथाशक्ति हो-हल्ला करने के बाबजूद जनता आपके साथ है. आप को हमारे सपनों का भारत देना है, जिसमें..

1. कुपोषित बच्चे न हों और कोई भी भूख से नहीं मरे.
2. प्रत्येक नागरिक का रहन-सहन शेष पेज 6 पर...

# यात्री सुविधा समिति के निरीक्षणों से खुल रही है अधिकारियों की कलई

सुरेश त्रिपाठी

रेलवे बोर्ड की यात्री सुविधा समिति (पीएसी) द्वारा अपने गठन के एक साल से भी कम समय के अंदर देश भर में भारतीय रेल के विभिन्न जोनों/मंडलों के तमाम स्टेशनों का धुआंधार निरीक्षण किए जाने से लगभग सभी मंडल रेल प्रबंधक और उनके शाखा अधिकारियों के साथ ही जोनल मुख्यालयों और रेलवे बोर्ड में बैठे कुछ बड़े अधिकारी भी यात्री सुविधाओं के फ्रंट पर अपनी कलई खुल जाने के डर से इतना घबरा गए हैं कि अब वे यात्री सुविधा समिति के सदस्यों के दौरों को सीमित और बाधित करने की साजिशें रचने लगे हैं. समिति के दौरों पर चेयरमैन की पूर्वानुमति जैसी बंदिशें लगाई जाने लगी हैं. जबकि समिति के कई सदस्यों ने इस दरम्यान अपने निरीक्षणों में वह कमियां देखीं और उनमें सुधार के निर्देश दिए हैं, जिन्हें स्थानीय रेल अधिकारियों को खुद देखना चाहिए था.

जैसे स्टेशनों पर एफओबी की टूटी टायल्स, एफओबी के ऊपर शेड एवं लाइट की उचित व्यवस्था करना, प्रतीक्षालय में बाल्टी एवं मग उपलब्ध कराना, फर्नीचर बदलना, प्लेटफार्मों के कैटरिंग स्टालों पर नए एवं स्पष्ट रेट बोर्ड लगवाना, शिकायत हेतु फोन नंबर अंकित किया जाना, गुड्स शेड की एप्रोच रोड की मरम्मत करना, एफओबी पर चढ़ने के स्लोप को ठीक से बनाना, प्लेटफॉर्म्स के लेवल को ऊंचा करना, टायलेट में नल की टोंटी बदलवाना तथा प्लेटफार्म पर वाटर बूथ की आवश्यकता की पूर्ति करना, स्टेशनों पर यात्रियों द्वारा आरक्षण काउंटर की कार्य अवधि को बढ़ाए जाने पर विचार करना, प्लेटफॉर्म्स पर यूरिनल सिस्टम लगाना, शौचालय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, यात्रियों द्वारा आरक्षण केंद्र की मांग को पूरा करना आदि शामिल हैं.

इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय के स्नानगृह एवं टायलेट में बाल्टी, मग एवं चौकी रखवाना, पार्किंग स्टैंड में किराया सूची (रेट बोर्ड) लगवाना तथा उसे द्विभाषी लिखवाना, रेलवे उद्यानों का सुंदरीकरण करना, कुली विश्राम गृहों के आसपास की गंदगी को साफ कराना, स्टेशनों की सरकुलेटिंग एरिया तथा स्टेशनों/प्लेटफार्मों का गहन निरीक्षण करना, निरीक्षण के दौरान स्टेशनों पर स्थित खानपान स्टाल, यात्री विश्रामालय, रिटायरिंग रुम, जन-आहार, गार्ड-ड्राइवर लाबी, टिकट बुकिंग आफिस आदि की साफ-सफाई के साथ ही उनकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना, यात्री विश्रामालय हॉल में चार्जिंग पॉइंट बढ़ाना, स्टेशनों की व्यवस्था में आवश्यक सुधार, ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने, यात्रियों द्वारा की गई मांगों को पूरा करने आदि यात्रियों की मूलभूत जरूरतों एवं अन्य तमाम आवश्यक विषयों पर यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने न सिर्फ संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं, बल्कि उपरोक्त तमाम कमियों के बने रहने पर जबरदस्त झाड़ भी लगाई है.

रेलवे यार्डों, मरम्मत कारखानों, धुलाई-सफाई साइडिंग्स आदि में तमाम कमियों और वहां चल रहे भ्रष्टाचार पर भी यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने उंगली उठाई. अमृतसर साइडिंग के निरीक्षण के दौरान वहां चल रहे भ्रष्टाचार को सदस्यों द्वारा संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाया जाना उन अधिकारियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति है, जिनके मातहत यह सब वर्षों से चल रहा है. गाड़ियों की सफाई और धुलाई के लिए दिए गए ठेकों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित से 80% कम आदमी लगाया जाना और आपस में उसकी बंदरबांट करना भी सदस्यों द्वारा उजागर किया गया. समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों के निरीक्षण के दौरान रेलवे की जमीन पर हजारों अवैध कब्जों सहित पुराने निर्माणों में करोड़ों का खर्च दिखाकर भी उनका जस का तस रहना भी उजागर हुआ है.

पश्चिम रेलवे के बोरीवली स्टेशन पर पांच से सात करोड़ के काम की लागत को 55 करोड़ बताया जाना भी हाल ही में समिति के सदस्यों ने उजागर किया. इस मामले में समिति के सदस्यों ने जब प्लान मंगवाया, तब पता चला कि अधिकारीगण बोरीवली स्टेशन पर बनने वाले एफओबी की दोनों तरफ की दीवारों पर कांच के पारदर्शी पैनल लगाने वाले हैं. इस पर समिति के सदस्यों ने ऐतराज जताया. इसके अलावा इन पैनल्स के रिफ्लेक्शन से मोटरमैनों/ड्राइवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि रेलवे ने दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच बनी कुछ निजी इमारतों में लगाए गए ऐसे ही ग्लास पैनल्स पर कड़ा ऐतराज जताया था. अधिकारियों के इसी प्रकार के फालतू खर्चों पर जब समिति के सदस्य ऐतराज जताते हैं, तो उन्हें यह नागवार लगता है. इसी दौर में समिति के सदस्यों ने मध्य रेलवे के परेल स्टेशन के पुराने एफओबी को देखकर हैरानी जताई, जहां दोनों प्लेटफॉर्म्स में एकसाथ लोकल आ जाने पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में कम से कम 40 से 45 मिनट लग रहे हैं. यह एफओबी कभी भी चरमराकर ढह सकता है. समिति के सदस्यों ने तत्काल डीआरएम और एडीआरएम को इस समस्या का समाधान करने को कहा. इस पर उक्त दोनों अधिकारियों ने इसे अगले तीन दिनों में ठीक कर दिए जाने की हामी भारी थी, मगर समस्या आज भी जस की तस है. किसी ने कुछ नहीं किया. इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि संबंधित अधिकारीगण उक्त जैसे किसी एफओबी के अचानक ढहने और उसमें दबकर सैकड़ों निर्दोष यात्रियों के मरने तथा इस प्रकार से रेलमंत्री को बदनाम किए जाने का इंतजार कर रहे हैं. इसी प्रकार हार्बर लाइन पर चेम्बूर स्टेशन ईस्ट साइड में यात्रियों के निकलने के लिए प्लान के अनुसार 100 फुट का रास्ता है, मगर यहां करीब 80 फुट में रेलवे ने दूकानों का आवंटन कर दिया. समिति के सदस्यों ने अपने निरीक्षण के दौरान इन दूकानों का रेनुअल नहीं किए जाने और उन्हें वहां से

- यात्री सुविधा समिति के निरीक्षणों को बाधित करने की हो रही है साजिश
- समिति के सदस्यों पर दौरे पर जाने से पहले बंदिशें लगाने की हो रही कोशिश
- ज्यादा कलई खुल जाने के डर से घबराए हुए हैं रे.बो./जोनल रेलों के अधिकारी
- सैकड़ों रेल यात्रियों के मरने और रेलमंत्री के बदनाम होने का किया जा रहा इंतजार
- समिति सदस्यों के साथ बैठक करने के बजाय डीआरएम चले गए पिकनिक मानाने

हटाकर यात्रियों के लिए प्रॉपर पैसेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. तथापि, जहां कुछ दूकानों का रेनुअल कर दिया गया, वहीं तोड़ी गई दूकानों को हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया. इसका मतलब यह है कि जहां दूकानों के रेनुअल में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं अदालतों में रेलवे का पक्ष मजबूती के साथ रखने में भारी कोताही की जा रही है. रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे मुख्यालय की नाक के नीचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विगत दिनों किए गए निरीक्षण में भारी कमियां उजागर हुईं. मुंबई के तमाम उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर भारी कमियां समिति के सदस्यों ने उजागर करके संबंधित रेल अधिकारियों को अवगत कराया. पिछले हफ्ते इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन सहित उत्तर मध्य रेलवे के अन्य स्टेशनों पर समिति के सदस्यों द्वारा किए गए निरीक्षण में उपरोक्त जैसी तमाम सामान्य कमियां उजागर हुईं, जिन्हें सामान्य तौर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दैनंदिन कामकाज के तहत पूरा किया जाना चाहिए था. मगर इन कमियों को यात्री सुविधा समिति के सदस्य उजागर करके उन्हें ठीक करने का निर्देश दे रहे हैं. यह संबंधित अधिकारियों के लिए शर्म की बात इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि यात्री सुविधा के नाम पर ही वह न सिर्फ सबसे अधिक फंड खर्च कर रहे हैं, बल्कि उसकी बंदरबांट भी कर रहे हैं.

रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि यात्री सुविधा समिति के कुछ सदस्य जब विगत दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए जयपुर जा रहे थे, तब रेलमंत्री सेल में बैठी चौकड़ी के एक सदस्य द्वारा अपने ससुर की पूर्व सेक्रेटरी का वहां एक मंडल में प्रमुख पद पर होने के मद्देनजर उनसे वहां खासतौर पर में कुछ नहीं करने को कहा गया था. सूत्रों का कहना है कि उसके बाद से समिति ने उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ मुंह भी नहीं उठाया. सूत्रों ने बताया कि इसी दरम्यान समिति के सेक्रेटरी द्वारा की गई एक साजिश के अंतर्गत समिति के चेयरमैन का किसी के माध्यम से इस्तीफा मांग लिए जाने का प्रकरण भी उजागर हुआ, जिसके तहत समिति के सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हर महीने एक नियत तारीख को पूरे रेलवे बोर्ड के साथ यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन एवं सभी सदस्यों की बैठक होती है. इस बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा अपने निरीक्षणों के दौरान आए अनुभवों को पूरे रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा जाता है. इसके बाद मदवार यात्रियों की सभी समस्याओं पर रेलवे बोर्ड के संबंधित अधिकारियों से जवाबतलब किया जाता है अथवा उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया जाता है. बताते हैं कि ऐसी ही एक बैठक में समिति के कुछ सदस्यों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान डीआरएम के उपस्थित न रहने का मामला उठाया गया. इस पर उन्हें कहा गया कि निर्धारित व्यवस्था और परंपरा के अनुसार उनके लिए एडीआरएम स्तर तक का अधिकारी ही पर्याप्त है.

बताते हैं कि इस पर संबंधित सदस्यों ने मंडल की प्रमुख अथॉरिटी (डीआरएम), जो कि मंडल स्तर का कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, की उपस्थिति को आवश्यक बताते हुए उनके निरीक्षण के दौरान उसकी उपस्थिति को अनिवार्य बनाए जाने की मांग की. परंतु पता चला है कि न सिर्फ रेलवे बोर्ड को सदस्यों की इस उचित मांग पर ऐतराज है, बल्कि कई मंडल रेल प्रबंधक भी पीएसी सदस्यों के साथ निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने में अपनी हेठी समझ रहे हैं. इस संदर्भ में सोलापुर मंडल का उदाहरण देने योग्य है, जहां करीब दो महीने पहले समिति के दो सदस्यों ने जाने से पूर्व अपनी सूचना मंडल को भेज दी थी और मंडल रेल प्रबंधक के साथ बैठक करके यात्री सुविधा संबंधी समस्याओं पर चर्चा किए जाने को कहा था, तथापि उनके वहां पहुंचने से पहले मंडल रेल प्रबंधक अपनी 'दूसरी बीवी' के साथ पिकनिक मनाने निकल गए थे.

यात्री सुविधा समिति के सदस्यों द्वारा जिस बारीकी से स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, उससे एक तो यह लगता है कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु का असली काम यात्री सुविधा समिति ही कर रही है. दूसरे यह कि यात्री सुविधा के नाम पर रेल प्रशासन और उसके कुछ संबंधित अधिकारी न सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि इस मद में आने वाले फंड की बड़े पैमाने पर बंदरबांट हो रही है. इससे तमाम रेल अधिकारियों को अपनी पोल-पट्टी खुलती नजर आ रही है, जिससे वह बौखला गए हैं और अब वे यात्री सुविधा समिति के न सिर्फ दौरों या निरीक्षणों को सीमित अथवा बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इससे घबराकर उन्होंने यात्री सुविधा समिति के कुछ ईमानदार सदस्यों को बदनाम करने का भी प्लान बना लिया है. सूत्रों का कहना है कि इसी साजिश के तहत रेलमंत्री सेल की चौकड़ी के माध्यम से रेलमंत्री के कान भरने की कोशिश भी की जा रही है.

सूत्रों ने बताया कि इसी साजिश के तहत अब समिति के सदस्यों को अपने दौरों और निरीक्षणों के लिए समिति के चेयरमैन से पूर्व अनुमति लेने की बंदिश लगाई गई है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि समिति के चेयरमैन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिन्हें आवश्यक फंड और तमाम सहूलियतें उपलब्ध कराने का आश्वासन रेलवे बोर्ड के कुछ मेंबर्स सहित कुछ जोनल अधिकारियों ने दिया है. सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहले भी होता रहा है. ऐसे में यदि समिति के चेयरमैन इन रेल अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हों, तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है. सूत्रों का यह भी कहना है कि जब समिति के चेयरमैन से इस्तीफा मांग लिया गया था और वह खुद इसी साजिश का शिकार होने से बचे थे, तब भी वह इन रेल अधिकारियों और रेलमंत्री सेल की चौकड़ी का खेल समझने में नाकाम हो रहे हैं, यह अवश्य आश्चर्य की बात है.

इस संबंध में जब 'रेलवे समाचार' ने रेलवे बोर्ड के कुछ समझदार अधिकारियों से बात की, तो उनका भी यही कहना था कि समिति के कई सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अब उनका यही अच्छा काम रेलमंत्री सेल की चौकड़ी और कुछ बेईमान रेल अधिकारियों को खलने लगा है. उन्होंने बताया कि इसीलिए व्यंग्य में रेलमंत्री सेल की चौकड़ी द्वारा समिति के सदस्यों से कहा जाता है कि 'लगता है कि वह रेलवे को पूरी तरह सुधार कर ही मानेंगे.' उनका यह भी कहना है कि यदि समिति के सदस्यों पर किसी प्रकार की भी बंदिश लगाई जाती है, तो यह रेलमंत्री के पावों में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होगा और यह काम रेलमंत्री सेल की चौकड़ी द्वारा बखूबी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है.

# बदलती जीवन शैली के चलते रेलकर्मी अपनी शारीरिक क्षमता खो रहे हैं –मनोज पांडेय

## झांसी वर्कशॉप में 'प्राणायाम, योगासन द्वारा तनाव प्रबंधन' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

**झांसी :** एशिया का सर्वाधिक वैगन मरम्मत करने वाले वैगन मरम्मत कारखाने के पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र में 'प्राणायाम एवं योगासन द्वारा तनाव प्रबंधन' कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में रेल मंत्रालय में सलाहकार प्रशिक्षण मनोज पांडेय मुख्य अतिथि थे. मुख्य कारखाना प्रबंधक अतुल्य सिंह ने कार्यशाला की अध्यक्षता की. श्री पांडेय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया. तत्पश्चात करुणेश श्रीवास्तव 'प्राचार्य/एसटीसी' ने अपने स्वागत संबोधन में जीवन में बढ़ रहे तनाव पर प्रकाश डाला.

मुख्य अतिथि मनोज पांडेय ने इस अवसर पर उपस्थित कर्मियों एवं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इंसान की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि उसके पास ठीक से सोने का भी समय नहीं है. देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठ जाना, लोगों की यह बहुत सामान्य दिनचर्या हो गई है, जिससे अनिद्रा और नींद की कमी स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि आज अधिकतम लोग इस बदलती जीवन शैली एवं परिवेश के चलते अपनी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा खो रहे हैं, ऐसे में 'चित्त या मन को एक जगह स्थिर करना ही योग है और योग एवं प्राणायम ही स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं.'

मुख्य कारखाना प्रबंधक अतुल्य सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्णरूप से स्वस्थ महसूस किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन तीनों के स्वस्थ रहने से आप अनेकों बीमारियों से दूर रहते हुए नव-ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, तो शारीरिक एवं मानसिक तनाव स्वयं ही दूर भाग जाता है और चंचल मन को भी काबू में रखता है. उन्होंने कहा कि प्राणायाम से आत्मीयता, उत्साह, धैर्य, एकाग्रता और याददास्त को भी बढ़ावा मिलता है. इसे प्रत्येक कर्मचारी को जीवन का अंग बनाना चाहिए, इससे आप अपने अंदर प्रसन्नता का संचार महसूस करेंगे.

इस अवसर पर सलाहकार प्रशिक्षण मनोज पांडेय ने एसटीसी में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि झांसी का पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है. पूर्व में यहां श्रीलंका रेलवे के पर्यवेक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हो चुके हैं. शीघ्र ही यहां की सुविधाओं को देखते हुए मोजाम्बिक और अफगानिस्तान के रेल प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यवेक्षकों को झांसी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है.

इस मौके पर पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र में नई तकनीक से सुसज्जित मॉडिफाइड आईसीएफ ट्राली एयर स्प्रिंग फिटेड वर्किंग मॉडल का उद्घाटन मनोज पांडेय ने किया. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर एमएलआर ए. डब्ल्यू. खान, उप वित्त सलाहकार अनिल एम. वजीरानी, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर बी. पी. एस. भदौरिया, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अनिल कुमार छापोलिया, मुख्य अनुदेशक डी. एन. वर्मा, वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर आफाक अहमद उपस्थित थे. समारोह का संचालन वरिष्ठ अनुदेशक नवीन शुक्ला ने वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी जी. आर. अहिरवार ने आभार व्यक्त किया.

# सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी...

**पेज 4 का शेष...** यह है कि वह 12-12 घंटों से लेकर 15-15 घंटों तक देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं और इसका ठीकरा कोहरे पर फोड़ा जा रहा है. जबकि साइबेरिया, जापान, रूस और चीन, जहां वर्ष भर सर्दियों का मौसम रहता है, में कभी गाड़ियां लेट नहीं होती हैं. पिछले 15-20 वर्षों से यह कहकर देश की जनता को रेलवे बोर्ड द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है कि कोहरे के दौरान 'क्लियर विजन' की तकनीक लाई जा रही है. परंतु यह आज तक नहीं आ पाई है और हर साल यात्रियों को सर्दियों में कोहरे के दौरान यात्रा में भयंकर परेशानी झेलनी पड़ रही है. रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस (एसीडी) का खूब ढ़ोल पीटा गया, यहां तक कहा गया कि इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद रेल दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सका है. तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ही रेलवे, एक ही मंडल, एक ही शहर में 15-15, 20-20 सालों से भ्रष्ट अधिकारियों का जमा हुआ होना और उनके मन में सरकार एवं प्रशासन का कोई भी डर नहीं होना है. इसके साथ ही सिफारिशों के आधार पर नाकाबिल अधिकारियों की पोस्टिंग किया जाना भी इसके लिए एक मजबूत और जिम्मेदार कारण है. अब जहां तक रेलवे में सिक्योरिटी (सुरक्षा) की बात है, तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, जिसने कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय मानते हुए फर्जी और गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक कारण के तहत रेलवे में दोहरी सुरक्षा व्यवस्था को पिछले 70 सालों से कायम कर रखा है. इसी असंवैधानिक व्यवस्था के चलते आए दिन चलती गाड़ियों में यात्रियों को लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी, हत्या और बलात्कार जैसे कुकृत्य हो रहे हैं. लगभग पूरी भारतीय रेल में अवैध हाकरों की भरमार है, जो कि न सिर्फ यात्रियों को अखाद्य बेच रहे हैं, मौका पाकर उन्हें लूट रहे हैं, बल्कि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी जुड़ा है. रेल प्रशासन उपरोक्त सभी कारण जानते हुए भी चुप है. यदि उसे कोई समझदार व्यक्ति कुछ सही सलाह भी देता है, तो वह अपने नौकरशाही के अहंकार के नशे में इतना चूर है कि उसे उचित-अनुचित की समझ ही नहीं हो रही है. भारतीय रेल की उपरोक्त तमाम दुर्दशा को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान रेलमंत्री सुरेश प्रभु अब तक के सबसे असफल रेलमंत्री साबित हो रहे हैं, जिन्हें एक अकाउंटेंट होने के नाते फर्जी आंकड़े और फर्जी दस्तावेज बनाने तथा प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रोफाइल ठीक दिखाने की महारत हासिल है.

# रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फेलियर के बारे में सूचित करने पर 1000 रुपए का इनाम

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण सक्सेना के मार्गदर्शन में रेल संरक्षा के क्षेत्र में जागरुकता हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं. संरक्षा के प्रति प्रोत्साहन हेतु श्री सक्सेना ने घोषणा की है कि हर उस व्यक्ति, चाहे वह रेलवे कर्मचारी हो, या कोई बाहरी व्यक्ति, यदि उसके द्वारा रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फेलियर के बारे में रेल प्रशासन को सूचित किया जाएगा, तो उसे महाप्रबंधक द्वारा 1000 रु. का नगद इनाम दिया जाएगा.

# हॉस्पिटल बेड पर भी दुनियादारी की चिंता में लगे हैं धरमवीर सिंह

**मुंबई :** पिछले करीब तीन महीनों से मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे धरमवीर सिंह को अपने अलावा संगठन और अन्य लोगों की बहुत चिंता लगी रहती है. देश भर से उन्हें मिलने आने वालों सहित स्थानीय आरपीएफ कर्मियों की वहां लगातार हाजिरी से हालांकि उन्हें आराम का समय कम मिल पाता है, तथापि उन्हें अपनी कम, दूसरों की चिंता ज्यादा सताती रहती है. उल्लेखनीय है कि श्री सिंह ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष हैं. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे श्री सिंह के शुभचिंतक जल्दी से उनके स्वस्थ होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चार कीमो लेने के बावजूद उनके चेहरे पर कहीं भी कोई शिकन नहीं दिखाई देती है. डॉक्टरों के अनुसार अभी उन्हें दो कीमो और देने की जरुरत है. उसके बाद वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे.

ज्ञातव्य है कि 7 से 9 जनवरी तक आरपीएफ एसोसिएशन का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है. उसकी व्यवस्था संबंधी चिंता भी धरमवीर सिंह को लगी हुई है. वह लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी और राष्ट्रीय महासचिव यू. एस. झा के संपर्क में रहते हैं. एसोसिएशन की जनरल काउंसिल की चित्रकूट में हुई पिछली बैठक में भी श्री सिंह को लगभग सभी पदाधिकारियों ने मंच से याद किया और उनकी कमी को भी महसूस किया था. सबका ख्याल रखने और सबके हितों की सतत देखभाल करने वाले श्री सिंह का जनसंपर्क इतना विशाल है कि उनका मोबाइल लगातार बजता रहता है. इसके बावजूद वह बिना किसी हिचक या परेशानी के सबकी बात सुनते हैं. परेल वर्कशॉप कॉलोनी स्थित आशियाने को श्री सिंह ने एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया है, जहां अब स्वस्थ ऊर्जा का संचार हो रहा है और तमाम कैंसर मरीज वहां स्वास्थ्य लाभ करके उन्हें धन्यवाद देकर आ-जा रहे हैं. ईश्वर ऐसे परोपकारी धरमवीर सिंह को जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे.

# प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक खुला पत्र

**पेज 4 का शेष...** सम्मानजनक स्तर का हो.

3. शिक्षा पर आने वाला व्यय आम लोगों की पहुंच में हो और शिक्षा उत्तम हो.
4. बुजुर्गों की समुचित देखभाल हो और उन्हें जीवनयापन के लिए पर्याप्त पेंशन मिले.
5. न्याय तुरंत या तय समय सीमा में मिले और वकीलों की मोटी फीसों का मोहताज न हो.
6. अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र लोगों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ करें, न कि उनके कपड़े उधेड़ें.
7. देश में सांप्रदायिक एवं जातीय सद्भावना हो तथा अपने पड़ोसियों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हों.
8. कोई भी रिश्वत मांगने का साहस न कर सके और न ही किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता पड़े.
9. संतोषजनक नागरिक सुविधाएं सभी नागरिकों को आसानी से सुलभ हों. यह पहले की तरह रिश्वत के पाये पर खड़ी न हों.

यह है मेरे सपनों का भारत ! मै जानता हूं कि यह सब करना कोई आसान काम नहीं, कहना आसान है. परंतु प्रधानमंत्री जी, ऐसा करने का वचन आपने स्वेच्छा से दिया है. भारत के लोग आपकी पुकार पर आगे आए हैं. वे घंटों पंक्तिबद्ध होकर तमाम तकलीफों का सामना कर रहे हैं. इस क्रम में वे अपने प्राणों का बलिदान भी कर रहे हैं, जिसके सामने आपका स्वघोषित बलिदान तुच्छ है.

यह कहना अनुचित न होगा कि दर्जनों निर्दोष भारतीयों को जान गंवाने के लिए आपके सलाहकारों ने और इस देश की नौकरशाही ने मूर्खतापूर्ण और कोताही से भरपूर कार्यान्वयन के द्वारा विवश किया है. यदि आप में जरा भी संवेदलशीलता है, तो इन निरीह लोगों का बलिदान, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग थे, आपको ताजीवन विवश करेगा कि आप बड़े भ्रष्ट लोगों पर कार्यवाही करें और संस्थागत भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करें.

हम आशा करते हैं कि केवल आम जनता, कालेधन के साथ जीना जिसकी आदत बना दी गई थी या बन गई थी, पर ही हमला करके आप चुप नहीं बैठ जाएंगे. यदि अब भी आप ऐसा नहीं करते हैं और पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, तो आप अपने से पूर्व और समकालीन अन्य नेताओं से भी बड़े धूर्त और पाखंडी सिद्ध होंगे. जो जनता आज आपको सिर आंखों पर बिठा रही है, वह आपकी हकीकत और असली रूप जल्द ही समझ जाएगी. इतिहास भाड़े के टट्टुओं द्वारा नहीं लिखा जाएगा.

नोटबंदी की घोषणा करते हुए आपने खुलेआम देश से कई झूठ बोले हैं. आपने कहा था कि 24 नवंबर के बाद से नोट बदलने की सीमा 4000 रुपयों से बढ़ा दी जाएगी, पर इसको समाप्त ही कर दिया गया. आपने कहा था कि रात्रि 12 बजे के बाद कलाधन कागज के टुकड़े होकर रह जाएगा, परंतु बाद में आयकर संशोधन क़ानून के द्वारा उसे सफ़ेद करने का प्रावधान कर दिया. आप समझ सकते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कितना शर्मनाक है ! उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने झूठों से बाहर निकलेंगे और एक उच्चकोटि के सेल्समैन के साथ एक स्टेट्समैन भी बनकर दिखाएंगे, जिसकी क्षमता आप में है. आवश्यक साहस तो आप में है ही. तभी आप अपने वचनानुसार हमें हमारे सपनों का भारत दे पाएंगे. आपको 125 करोड़ भारतीयों की अपेक्षा पर अब खरा उतरना ही होगा.

एक भारतीय नागरिक
**अतुल कुमार**

02.12.2016

# रेलवे में सेफ्टी का महाघोटाला...

**पेज 1 का शेष...** ओएचई मास्ट पिछले दिनों टूटकर दो भागों में विभक्त हो चुका है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले इस मामले की रिपोर्ट सीपीडी/आरई, चेन्नई ने की थी. इसके बाद डिप्टी सीई/आरई, मेरठ, उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीई/आरई, अहमदाबाद, गुजरात, डिप्टी सीई/आरई, जबलपुर, मध्य प्रदेश, डिप्टी सीई/आरई, कन्नूर एवं चेन्नई, तमिलनाडु और डिप्टी सीई/आरई, अंबाला एवं जम्मू ने भी इसकी रिपोर्ट दर्ज की है. इसके अलावा उपलब्ध कागजात से यह भी जाहिर है कि कोर के भंडार नियंत्रक (सीओएस) ने भी कंपनी के विरुद्ध कदम उठाए जाने की बात अपनी रिपोर्ट में कही है.

उल्लेखनीय है कि 'रेलवे समाचार' के पास उपलब्ध संबंधित कागजात के अनुसार इस मामले की जानकारी करीब एक साल पहले ही कोर और रेलवे बोर्ड सहित राइट्स को भी हो चुकी थी, तथापि आज एक साल बाद भी कंपनी द्वारा न सिर्फ कम वजन और कम मोटाई के ओएचई स्ट्रक्चर की आपूर्ति की जा रही है, बल्कि इतना बड़ा सेफ्टी हैजर्ड होने के बावजूद न सिर्फ कंपनी को, बल्कि कंपनी से ऐसे ओएचई स्ट्रक्चर की खरीद कर रेलवे में लगाने वाले संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कोर द्वारा बकायदे भुगतान किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मेंबर ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड के समय संबंधित कंपनी को पार्ट-1 से हटाकर पार्ट-2 कर दिया गया था, परंतु उनके रिटायर होने के तुरंत बाद कंपनी को पुनः पार्ट-1 का तमगा दे दिया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए निर्धारित और मान्य स्टैंडर्ड से कम वजन एवं कम मोटाई वाले ओएचई स्टील स्ट्रक्चर की जानकारी कोर के देश भर में स्थित 11-12 चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (सीपीएम) की रिपोर्ट से एक साल पहले ही कोर मुख्यालय को मिल गई थी. इसके बावजूद रेलवे बोर्ड अथवा कोर की तरफ से कंपनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया. इसके अलावा कंपनी द्वारा वर्तमान में भी कम वजन एवं कम मोटाई वाले ओएचई स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति की जा रही है. जबकि राइट्स द्वारा आज भी पूर्ववत इनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और रेलवे (कोर) द्वारा कंपनी एवं कॉन्ट्रैक्टर्स को लगातार भुगतान भी किया जा रहा है.

जाहिर है कि जानबूझकर रेल संरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है. 100-110 किमी. की गति से भागती किसी ट्रेन पर यदि इनमें से एक भी कमजोर ओएचई स्टील स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया, तो उक्त सेक्शन के सारे स्ट्रक्चर उसी गति से टूटकर ट्रेन पर गिर पड़ेंगे. इससे न सिर्फ सारी ट्रेन भक्क से जल उठेगी, बल्कि उसमें सवार हजारों रेलयात्रियों की देह जलकर खाक हो जाएगी, क्योंकि यह स्ट्रक्चर ट्रेन के इंजन को 25 हजार वोल्ट विद्युत की आपूर्ति कर रहे होते हैं. ऐसी भयानक तस्वीर की कल्पना करके ही जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब वास्तविक दृश्य कैसा होगा, उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है. उल्लेखनीय है कि पिछले करीब

छह सालों में लगभग एक लाख मीट्रिक टन सब-स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी उक्त मटीरियल की आपूर्ति के लिए कोर द्वारा अप्रूव्ड सोर्स है, जिसकी फाइनल सूची जीएम/कोर द्वारा अप्रूव की जाती है.

जानकारों का कहना है कि कम वजन एवं कम मोटाई का मटीरियल (ओएचई स्ट्रक्चर) आज भी कंपनी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और रेलों द्वारा लगाया भी जा रहा है तथा उसका भुगतान भी किया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि कंपनी द्वारा राइट्स और कोर के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कम वजन और कम मोटाई का मटीरियल न सिर्फ सप्लाई किया जा रहा है, बल्कि लगाया भी जा रहा है. जाहिर है कि पब्लिक सेफ्टी के साथ वृहद स्तर पर खुला खिलवाड़ किया जा रहा है. एक साल पहले इसकी पूरी जानकारी मिलने के बावजूद इस भयंकर सेफ्टी घोटाले पर रोक नहीं लगाई जा सकी है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रेलवे में किस कदर लूट चल रही है. कंपनी द्वारा कम वजन और कम मोटाई का मटीरियल सप्लाई किया जा रहा है, जब यह बात रेलवे बोर्ड अथवा कोर के अधिकारियों को समझ में आ गई थी, तब भी उन्होंने इसका कोई जॉइंट प्रोसीजर ऑर्डर (जेपीओ) जारी नहीं किया. हालांकि यह जेपीओ जीएम/कोर को जारी करना चाहिए था. इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि जीएम/कोर और राइट्स के संबंधित अधिकारी कंपनी को खुला सपोर्ट कर रहे हैं? जेपीओ का मतलब यह होता है कि जहां-जहां कंपनी द्वारा उक्त मटीरियल की सप्लाई की जा रही है, वहां-वहां जेपीओ के अंतर्गत कंपनी से आने वाले मटीरियल का वजन किए जाने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि इसी तरह जब वी. के. इंडस्ट्रीज द्वारा आपूर्ति किए गए कॉपर कंडक्टर की लेंथ (लंबाई) करीब 100 मीटर कम पाई गई थी, तो न सिर्फ तुरंत जेपीओ बनाया गया था, बल्कि कंपनी का भुगतान भी उसी औसत में कम कर दिया गया था.

इस संदर्भ में कोर का पक्ष जानने के लिए 'रेलवे समाचार' ने कोर के महाप्रबंधक एस. पी. त्रिवेदी और सीएओ(सीईई) ओमपाल को उनके मोबाइल पर संपर्क किया. ओमपाल ने संदर्भ सुने बिना ही कॉल खत्म कर दी, जबकि महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी का कहना था कि वह फिलहाल मुख्यालय से बाहर हैं, वापस पहुंचने पर वह मामले की जानकारी करेंगे और उचित कदम उठाया जाएगा. जबकि राइट्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) प्रभात आर. देव का कहना था कि जब तक राइट्स का फाइनल इंस्पेक्शन होता, तब तक कंपनी ने मटीरियल की सप्लाई भेज दी थी. इस पर जब यह कहा गया कि जब फाइनल मटीरियल का इंस्पेक्शन करने से पहले राइट्स द्वारा प्रोडक्शन स्तर पर तीन बार प्रोडक्शन मटीरियल का इंस्पेक्शन किया जाता है, तब अंडर वेट एवं अंडर क्वालिटी मटीरियल की सप्लाई कैसे संभव हुई? इस पर श्री देव का कहना था कि इस सारे मामले की जांच चल रही है और इस संबंध में उन्होंने कोर विजिलेंस को भी पत्र लिखा है.

# जीएम पोस्टिंग में फंसा रेलवे बोर्ड की...

**पेज 1 का शेष...** सेवानिवृत्त होने एक महाप्रबंधक की पोस्ट और खाली हो जाएगी. इसके साथ ही आरडीएसओ के डीजी की पोस्ट भी फरवरी में ही खाली हो रही है. रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि इस दरम्यान दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के लिए वी. के. यादव और उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के लिए आर. के. कुलश्रेष्ठ की महाप्रबंधक के पद पर पोस्टिंग के लिए उनके नाम पीएमओ को भेजे गए हैं. मगर इससे पहले कैट ने मगरूब हुसैन (आईआरएसईई, डीओबी-29.03.1959, डीआईटीएस - 27.03.1982) और विश्वेश चौबे (आईआरएसई, डीओबी-1.7.1960, डीआईटीएस-11.05.1982) के नाम जीएम पैनल-2016-17 में 31 मार्च 2017 से पूर्व शामिल किए जाने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही कैट ने यह भी आदेश दिया है कि आपात स्थितियों में और यदि जरुरत महसूस की जाती है, तो मगरूब हुसैन से जूनियर अधिकारी की महाप्रबंधक पद पर पोस्टिंग की जा सकती है, मगर उससे पहले श्री हुसैन के लिए एक पोस्ट खाली रखी जानी चाहिए. बोर्ड के सूत्रों ने यह भी बताया कि रेलवे बोर्ड ने कैट को यह लिखित आश्वासन देकर स्वीकार किया है कि श्री हुसैन को न सिर्फ जीएम पैनल में एनरोल किया जाएगा, बल्कि उन्हें महाप्रबंधक भी बनाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि श्री हुसैन, वी. के. यादव से वरिष्ठ हैं, जीएम पैनल में एनरोल होने पर उनका वरिष्ठता क्रमांक श्री यादव की जगह 23 होगा, जबकि श्री चौबे का वरिष्ठता क्रमांक एस. एस. स्वाइन के नीचे 28 होगा. इसके साथ ही यह भी महसूस किया जाता है कि कैट के आदेश एकदम स्पष्ट नहीं होने से सरकार और प्रशासन को अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाती है.

दक्षिण मध्य रेलवे की पहले खाली हुई जीएम पोस्ट पर श्री यादव को और उत्तर रेलवे की पोस्ट पर श्री कुलश्रेष्ठ को नामांकित करके श्री हुसैन की वरिष्ठता और कैट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. सूत्रों ने इसका मतलब यह निकाला है कि रेलवे बोर्ड श्री हुसैन को ओपन लाइन में नहीं, बल्कि किसी प्रोडक्शन यूनिट में जीएम बनाना चाहता है. उल्लेखनीय है कि फरवरी में आरडीएसओ के डीजी की पोस्ट भी खाली हो रही है, जहां रेलवे बोर्ड श्री हुसैन को भेजने की योजना में है. जबकि सूत्रों का यह भी कहना है कि श्री हुसैन को उनके पूरे कैरियर में कभी एक वार्निंग लेटर भी जारी नहीं हुआ है, उनका पूरा कैरियर एकदम साफ-सुथरा रहा है. यही स्थिति श्री चौबे के कैरियर की भी है, इसके बावजूद इन दोनों अधिकारियों को जीएम पैनल में शामिल नहीं किया गया. यह बात उन्हें जीएम पैनल फाइनल होने के बाद पता चली थी, तब उन्होंने कैट का रुख किया था.

यह तो सर्वज्ञात है ही कि जो भी अधिकारी अपने अधिकार और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, उसके प्रति रेलवे बोर्ड का रवैया एकदम से सौतेला और शत्रुतापूर्ण हो जाता है, फिर भले ही वह कितना भी ईमानदार या साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाला ही क्यों न रहा हो. इसकी मिशाल उक्त दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही महेश कुमार गुप्ता भी हैं. यह भी पता चला है कि श्री यादव उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बनने की इच्छा रखते हैं. कैट के आदेश के अनुसार यदि सही समय पर श्री हुसैन का जीएम पैनल में एनरोलमेंट किया जाए, तो उन्हें दक्षिण मध्य रेलवे और श्री यादव को उत्तर रेलवे का महाप्रबंधक बनने का मौका मिल सकता है. इसके बाद आर. के. कुलश्रेष्ठ और सच्चिदानंद सिंह को क्रमशः उत्तर मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भेजा जा सकता है. वर्तमान में इन चारों महाप्रबंधकों की पोस्टिंग एकसाथ किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाना ही वास्तव में सही निर्णय होगा. रेलवे बोर्ड के सूत्रों का यह भी कहना है कि वर्तमान कुछ महाप्रबंधकों में दहशत बनाए रखने और पोस्टिंग के लिए तैयार वरिष्ठ अधिकारियों को दिग्भ्रमित करने के लिए 'स्टोरकीपर' ने यह भी हवा गर्म की हुई है कि जिन महाप्रबंधकों के क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों के दरम्यान रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्हें दूसरे जोनों में अथवा रेलवे बोर्ड में शिफ्ट किया जा सकता है. जबकि यह बात सर्वज्ञात है कि जिन दो जोनों में पिछले दो महीनों के दरम्यान बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उन जोनों के महाप्रबंधक इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में यह बात समझ से बाहर है कि किन महाप्रबंधकों को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने का शगूफा स्टोरकीपर ने हवा में छोड़ रखा है? रेलवे की बदहाली का प्रमुख कारण स्टोरकीपर की पुनर्नियुक्ति और रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा जोनल महाप्रबंधकों को कठपुतली बना दिया जाना है.

# उ.प्र. के विकास हेतु 40,453 करोड़ का...

**पेज 1 का शेष...** हुए कहा कि मैंने रेल बजट में चार गाड़ियों को प्रारम्भ करने की घोषणा की थी, जिसमें एक 'हमसफर' ट्रेन भी थी. हमसफर की शुरूआत गोरखपुर से की जा रही है. हमसफर ट्रेनें भविष्य में अन्य स्थानों से भी चलाई जाएंगी. इस गाड़ी में चाय, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, सीसीटीवी, जीपीएस सिस्टम जैसी एडवांस तकनीकी भी लगाई गई है. इस ट्रेन में मटीरियल भी इस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है कि लोगों को सुविधा हो. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गाड़ियां चलाने तक ही हम सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 40,453 करोड़ रु. का रेल बजट दिया गया है. यहां तमाम तरह के विकास कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि रेलवे देशवासियों का ख्याल रखती है. अतः रेलवे के विकास में देशवासियों के सहयोग की जरूरत है. रेलमंत्री ने कहा कि स्कैलेटर लगभग हर स्टेशन पर लगाए जाएंगे.

इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने सभी उपस्थित गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जंक्शन स्टेशन है. विगत दो वर्ष गोरखपुर जं. स्टेशन के लिए स्वर्णिम समय रहा है. इस दौरान यहां उन्नत एवं आधुनिकतम सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं तथा बहुत सी सुविधाओं को प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि रेल बजट में यात्रियों को तीव्रगामी एवं आरामदेह यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रकार की नई गाड़ियों के संचलन की घोषणा की गई थी, इन गाड़ियों में प्रमुख है 'हमसफर' एक्सप्रेस है.

महाप्रबंधक ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा देश की प्रथम 'हमसफर' एक्सप्रेस को गोरखपुर से आनंदविहार टर्मिनस के बीच चलाए जाने का निर्णय लिया गया और आज इस गाड़ी का शुभारम्भ रेलवे बोर्ड से दूरवर्ती झंडी से एवं सांसद महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों हो रहा है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर-आनंदविहार टर्मिनस 'हमसफर' एक्सप्रेस में अत्याधुनिक जर्मन डिजाइन के एलएचबी रेक है तथा यह पूर्णतया एसी तृतीय श्रेणी युक्त ट्रेन है. कोचों का बाहरी स्वरूप विनायल रैपिंग कर काफी आकर्षक किया गया है तथा इसकी आतंरिक साज-सज्जा काफी सुंदर है. कोचों में खिड़कियों एवं बीच के मार्ग के पर्दे काफी आकर्षक हैं तथा कोचों में विभिन्न प्रकार के रंगो में सीटों तथा बर्थों को तैयार किया गया है और सीटों में मध्य गैप भी काफी अच्छा है.

स्टेशनों पर विशेष रूप से वृद्ध महिला एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे नित नई यात्री सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. इसी क्रम में गोरखपुर जं. के प्लेटफार्म-9 पर दो एस्कैलेटर लगाए गए हैं. महाप्रबंधक ने बताया कि इन एस्कैलेटरों को लगाए जाने का कार्य वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किया गया था। इस पर कुल 1.75 करोड़ रु. की लागत आई है. इसके पूर्व, यहां पर दो एस्कैलेटर मुख्य प्रवेश द्वार के निकट लगाए गए हैं. इस प्रकार यहां अब चार एस्कैलेटरों की सुविधा उपलब्ध हो गई है.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017



# वर्ष 2016-17 की निर्धारित परियोजनाओं को 31 मार्च तक पूरा किया जाए-जीएम

## पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही निर्माण परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन

**गोरखपुर ब्यूरो :** पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही निर्माण परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन महाप्रबंधक कक्ष में किया गया. बैठक में अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा, सभी विभाग प्रमुख और तीनों मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तथा निर्माण संगठन के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रहे विभिन्न आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नई रेल लाइन, रेल विद्युतीकरण, सड़क उपरिगामी पुल एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर कार्य प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने वित्तवर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित परियोजनाओं को 31 मार्च, 2017 तक पूरा करने का निर्देश दिया. महाप्रबंधक ने निर्माण कार्यों हेतु धन एवं सामग्रियों की आपूर्ति की समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि सामग्रियों की आपूर्ति के कार्य में तेजी लाई जाए तथा धन की उपलब्धता वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों के प्रयोग से सुनिष्चित की जाए. श्री मिश्र ने थावे-छपरा कचहरी लूप, गोंडा-बहराइच, पीलीभीत-टनकपुर सहित विभिन्न रेल खंडों के आमान परिवर्तन कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा इन खंडों को शीघ्र कार्य पूरा कर यात्री यातायात खोलने हेतु समय निर्धारित किया.

महाप्रबंधक ने डोमिनगढ़-गोरखपुर-कुसुम्ही रेल खंड हेतु स्वीकृत तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल हेतु स्वीकृत दूसरी लाइन के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का जायजा लिया तथा कार्य में तेजी लाने हेतु दिशा--निर्देश जारी किया. उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु निर्देश दिया. इस मौके पर उन्होंने स्वीकृत हुई नई विद्युतीकरण परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का निर्देश भी दिया. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे पर निर्माणाधीन सड़क उपरिगामी पुलों तथा लो-हाइट सब-वे के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत करने हेतु दिशा--निर्देश दिया. उन्होंने गोरखपुर स्टेशन के निकट कौवाबाग में बनने वाले सब-वे के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने को कहा. बैठक में निर्माण संगठन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्य के दौरान आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु महाप्रबंधक का दिशा-निर्देश प्राप्त किया.

# यात्री सुविधा समिति द्वारा नैनी-मिर्जापुर सेक्शन एवं इलाहाबाद स्टेशन का निरीक्षण

**इलाहाबाद ब्यूरो :** रेलवे बोर्ड की यात्री सुविधा समिति (पीएसी) के सदस्य योगेश शुक्ला, प्रभु नाथ चौहान, रामाधीन सिंह एवं सुधीर मिश्र ने 20 दिसंबर को नैनी, भीरपुर, मेजा रोड, मांडा रोड, विन्ध्याचल एवं मिर्जापुर स्टेशनों का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सदस्यों ने नैनी स्टेशन पर एफओबी की टूटी टायल्स को बदलने तथा एफओबी के ऊपर शेड एवं लाईट की व्यवस्था करने, प्रतीक्षालय में बाल्टी एवं मग उपलब्ध कराने, फर्नीचर बदलने, प्लेटफार्म नं. 4 पर स्थित कैटरिंग स्टाल पर नया रेट बोर्ड लगाने तथा शिकायत हेतु नंबर अंकित किए जाने के निर्देश दिए.

सदस्यों ने नैनी गुड्स शेड की एप्रोच रोड की मरम्मत कर उसे ठीक करने को भी कहा तथा एफओबी पर चढ़ने के स्लोप को ठीक से बनाने पर जोर दिया. उन्होंने भीरपुर स्टेशन के लेबल को ऊँचा करने एवं टायलेट में नल तथा प्लेटफार्म पर वाटर बूथ की आवश्यकता बताई. मेजा रोड स्टेशन पर यात्रियों द्वारा आरक्षण काउंटर की कार्य अवधि को बढ़ाए जाने की मांग की गई. प्लेटफार्म नं. 2/3 के लेबल को ऊँचा करने, प्लेटफार्म नं. 4 पर यूरिनल सिस्टम लगाने तथा पानी की व्यवस्था की मांग की गई, जिसे सदस्यों ने फौरन पूरा किए जाने के निर्देश दिए.

मांडा रोड स्टेशन पर यात्रियों द्वारा आरक्षण केंद्र की मांग की गई, प्लेटफार्म नं. 1/2 पर शौचालय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश तथा मूरी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की गई. इसके साथ ही सदस्यों ने विन्ध्याचल स्टेशन पर आवश्यक सुधार के भी निर्देश दिए. मिर्जापुर स्टेशन पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय के स्नानगृह एवं टायलेट में बाल्टी तथा मग रखने को कहा. पार्किंग स्टैंड में रेट बोर्ड को द्विभाषी में लिखने, शास्त्री उद्यान के सुंदरीकरण के लिए कहा तथा कुली विश्राम गृह के बगल में गंदगी को तत्काल साफ कराने के निर्देश दिए.

### सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी पूरी नहीं होती हैं यात्रियों की सामान्य जरूरतें

अगले दिन 21 दिसंबर को समिति के सदस्यों ने इलाहाबाद जं. स्टेशन के सिटी साईड एवं सिविल लाईन साइड की सरकुलेटिंग एरिया तथा स्टेशन का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सदस्यों ने स्टेशन पर खानपान स्टाल, यात्री विश्रामालय, रिटायरिंग रुम, जन-आहार, गार्ड-ड्राइवर लाबी, बुकिंग आफिस आदि का बारीक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान यात्री विश्रामालय हॉल में चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए, साईकिल स्टैंड पर रेट बोर्ड को नया लगाने तथा स्टेशन पर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए.

तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज तथा अन्य अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों के बीच बैठक का आयोजन किया गया. सर्वप्रथम वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी. के. मिश्रा ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से मंडल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. तत्पश्चात बैठक में सदस्यों ने इलाहाबाद से छिवकी के बीच बस चलाने पर विचार-विमर्श किया तथा ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने 20 दिसंबर को यात्रियों द्वारा की गई मांगों को पूरा करने पर जोर दिया. इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक ए. के. द्विवेदी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी. के. मिश्र, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अंशू पांडेय, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियन्ता अजीत सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता अमिताभ शर्मा, वरिष्ठ मंडल अभियन्ता सुनील कुमार गुप्ता सहित मंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. 'तारीफ यह है कि उपरोक्त जो चीजें यात्री सुविधा समिति के सदस्यों को एक ही दौरे में नजर आ जाती हैं, वह सम्बंधित रेल अधिकारियों को कभी नजर नहीं आती हैं, जबकि प्रत्येक जोनल रेलवे और मंडल मुख्यालय द्वारा यात्रियों की सुविधा के नाम पर प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च दिखाया जा रहा है.' मीटिंग के बाद यह कहना था समिति के एक सदस्य का.

# 'रेल कर्मचारियों को सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए'

**इलाहाबाद ब्यूरो :** उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभाकक्ष में रेलवे संगठन की बेहतरी के लिए 'पाजिटिव एटिट्यूट, संरक्षा तथा कस्टमर केयर' विषय पर 22 दिसंबर को एक सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार का आयोजन मंडल के परिचालन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, चंदौसी के अवकाशप्राप्त प्रशिक्षक महेशचंद्र उपाध्याय थे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिचालन एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया. प्रशिक्षण के दौरान श्री उपाध्याय ने बताया कि रेल कर्मचारियों को सदैव सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए तथा समय के अनुसार हो रहे परिवर्तनों के साथ हमें अपने अंदर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्राहकों (यात्रियों) के साथ हमेशा विनम्रतापूर्ण एवं शालीन व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे हम ग्राहकों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें. कर्मचारियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे शिकायत की स्थिति उत्पन्न हो. यदि विशेष परिस्थितियों में शिकायत की स्थिति उत्पन्न होती भी है, तो जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करना चाहिए. इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज, अपर मंडल रेल प्रबंधक ए. के. द्विवेदी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी. के. मिश्र, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक मनू प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव तथा टीआई अश्विनी द्विवेदी एवं आलोक पांडेय तथा मंडल के अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में परिचालन एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी
संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

● इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
● गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
● भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
● रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
● वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017